international trade and enforcement of labour standards through the imposition of the social clause. At the same time, the resolution recognised the necessity for commitment to promote measures to improve the working and living conditions of all people and provide better levels of protection. India is also a party to this resolution.

Unemployed persons in the country

934. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the total number of unemployed as on 31st December, 1994 according to the records maintained by the Employment Exchanges in the country;

(b) whether it is a fact that the Employment Exchanges have become places of nepotism and corruption and are not discharging their duties objectively; and

(c) if so, the steps Government propose to take to restructure the Employment Exchanges in the country?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) The total number of job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, on the live register of employment exchanges in the country, as on 31-12-1994 was 366.91 lakhs.

(b) and (c) Employment Exchanges function under the administrative control of State/U.T. Governments. Complaints of nepotism and corruption received in Government are promptly forwarded to the State/U.T. Governments for necessary action.

Action against loom owners for employing child llabour

935. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many cases have been instituted against loom-owners for the illegal employment of child weavers in the country;

(b) how many raids have been conducted in the carpet-belt against the exporters of carpet for employing child labour; and

(c) the details of the action taken thereon?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Bonded child labour in Mirzapur

936. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Kailash Satyarthi, Chirman of South Asian Coalition on Child Servitude has sent list of 2000 bonded child labour working in Mirzapur, Uttar Pradesh to the Prime Minister Secretariat;

(b) what aciton has been taken by Government against the law breakers; and

(c) what steps Government propose to take to set free and rehabilitate such child labourers of Mirzapur?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) A communication has been received from Shri Kailash Satyarthi enclosing a list containing 784 names of alleged child labour belonging to different districts of Bihar and U. P. who are stated to be working in carpet industry. The concerned State Governments of U.P. and Bihar have been asked

to constitute a joint task force to locate and verify the status of the persons named in the list within a time bound schedule and to take strong vigorous action according to law against those found violating the law simultaneously with rehabilitation of those found eligible for such assistance under the Centrally Sponsored Scheme.

रोजगार कार्यालय का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित किया जाना

937. श्री ईश दत्त यादव :
श्री आस मोहम्मद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के संबंध में हाल ही में कोई कदम उठाये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं । इनके द्वारा रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इनके कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। पंजीकरण एवं नियुक्ति के मामलों में सरलीकरण एवं एकरूपता के संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते हैं ।

श्रम दिवसों की हानि

938. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों में बढ़ते असंतोष को कम करने के लिये प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में कोई नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चुनिन्दा उद्योग समूहों में वर्ष 1994 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों की वजह से नष्ट हुए श्रम दिवसों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) से (ग) प्रबन्धन में कर्मचारियों की सहभागिता के लिए एक योजना भारत सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की गई थी जो विशेष रूप से छूट प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू है । योजना में शाप फ्लोर और प्लान स्तरों पर कर्मचारियों की सहभागिता की व्यवस्था है । जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का सम्बन्ध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग श्रम मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकते हैं । सहभागी व्यवस्था में प्रचालनात्मक क्षेत्र, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, कार्मिक मामले, कल्याण, पर्यावरण तथा समुदाय विकास शामिल हैं ।